श्री माधवराव सिंधिया : सर, अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मैं आपके सुझाव के बारे में अवश्य टाइम टेबल कमेटी को कह दूंगा कि इस पर विचार किया जाए । जहां तक कोचेज़ की अन्दरुनी हालत का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि रेलवे की सफलता जनता के सहयोग पर भी निर्भर है । कई ऐसे क्षेत्र हमारे देश में हैं कि जहां आपने कोई नया कोच आदि लगाया तो दो हफ्ते के अन्दर ही अन्दर पंखे गायब हो जाते हैं, बल्ब गायब हो जाते हैं यहां तक कि सीटों को चीर कर डनलप भी निकाल लिया जाता है । मेरी माननीय सदस्यों से हार्दिक अपील है और निवेदन है कि वे इस संबंध में जन-जागृति फैलाने का भी प्रयास करें ताकि हमें पूरा सहयोग मिले और हम अपनी ट्रेनों को अच्छी कंडीशन में चला पायें ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान उन ट्रेनों पर आकर्षित करना चाहूंगा जो ट्रेनें राजधानी को गुजरात से संबद्ध करती हैं । गुजरात को सर्वोदय एक्सप्रस और सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रैस जो है उससे सम्बद्ध करती है । मैं मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि यदि आपको समय मिले तो एक बार उसमें सफर कर लें इसलिए कि यहां से जब गुजरात पहुंचते हैं तो मान्यवर, वहां खिड़कियों का आलम यह है कि यहां से कोई भी यात्री उस पर सफर करना नहीं चाहता । इसलिए मैं खिड़कियों के डिज़ाइन को बदलने की मांग करूंगा क्योंकि जब अहमदाबाद या और जगह पर यह गाड़ी पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम धूल में खेलकर आये हों । यह स्थिति होती है । मान्यवर, दूसरी मांग गुजरात की यह है कि उसके साथ दो ए०सी० कोच लगाए जाएं और इतना लंबा समय काटने के लिए उसे पेंट्रीकार से भी सम्बद्ध नहीं किया गया है । यह हमारी पुरानी मांग है और इस मांग को सन्तुष्ट करने की अति आवश्यकता है । जो सर्वोदय एक्सप्रस चलती है उसको दो दिन के अलावा और समय देने की भी मैं मांग करता हूं

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय सदस्य के सुझाव के लिए मैं धन्यवाद करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: Other Members can send their suggestions to the Railway Minister. We will go to the next Question now. Question No. 25.

Voluntary organisations running non-formal education centres in Madhya Pradesh

*25. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of voluntary organisations which have been given grants by Government for running non-formal education centres in Madhya Pradesh during the years 1984-85 and 1985-86; and

(b) what is the number of these centres visited by officers of the Ministry during the same period separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) 11 Voluntary organisations were given grants during 1984-85 and three voluntary organisations during 1985-86 for running non-formal education centres in Madhya Pradesh.

(b) The officers/agencies of the Central and State Governments are authorised to inspect to work of these centres. While officers of the Ministry do not inspect the non-formal education centres themselves, the officers under National Institute of Educational Planning and Administration inspected six centres and officers of National Council of Educational Research & Training inspected 20 Centres in Madhya Pradesh in 1985-86.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मिनिस्ट्री आफ् एजूकेशन एंड कल्चर की एस्टीमेटस कमेटी 1985–86 की रिपोर्ट जो पेज

25 में प्रकाशित हुई है और जिसमें सरकार के लैटर नम्बर 1-6/84-1 स्कूल II, 8 अगस्त, 1984 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि एनसीईआरटी और फील्ड एडवाइजर्ज के माध्यम से वालेंट्री आर्गेनाइजेशन के निरीक्षण की व्यवस्था निर्धारित की जायेगी मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी व्यवस्था निर्धारित कर ली गयी है । यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और क्या सरकार ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट है ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, एन०सी०ई०आर०टी०, जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है कि हमारे विभाग के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है । हमारे देश में तकरीबन 2 लाख केन्द्र हैं और निरीक्षण, मंत्रालय के पदाधिकारी यद्यपि नहीं करते, परन्तु भारत सरकार की अपनी एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन एवम् निरीक्षण कराता है और इसलिए यह "नीपा" और एन०सी०ई०आर०टी० ने अपने गुणात्मक पुनर्गठन की योजना प्रारंभ कर दी हैं और यह रिपोर्ट तैयार कर रही है । विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसका भी आर्गेनाइजेशन किया जाएगा और इस महीने के अन्त तक इसकी उपलब्धि हो जायेगी ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने केसेज हैं, जिनमें वायण्टरी आर्गेनाइजेशन की ग्राण्ट मध्यप्रदेश में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में इस आधार पर रोकी गयी है कि (i) उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली है या (ii) उनकी आडटड स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट प्राप्त नहीं हुआ है या (iii) उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ ?

श्रीमती कृष्णा साही : सभापति महोदय, मध्यप्रदेश में सन् 1984-85 में 11 संस्थाओं को दिया गया है और 1985-86 में 3 को / 1985-86 में 3 वायण्टरी एजेंसी की वहां की सरकार ने अनुशंसा की है और उसके बाद 1985-86 में मात्र 3 को इसलिए दिया गया क्योंकि बाकी संस्थाओं की अनुशंसा राज्य-सरकार ने नहीं की और उनका यटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं पहुंच सका था । साथ ही साथ हमारे यहां जो इसके तीन आधार हैं राशि आवटित करने के, उसमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और आडिट रिपोर्ट का और इन दोनों में जब कमी पाई गई है तो बाकी को नहीं दिया गया है । बाकी तीन संस्थाओं का, जिनका मैंने बताया है, अगर माननीय सदस्य नाम चाहें तो मैं उनको दे सकती हूं । ये तीन संस्थाएं हैं, जिनको दिया गया है, उनके नाम हैं— सुलतान उल हिन्द एजुकेशनल एण्ड सोशल सरविस सोसाइटी, भोपाल इसकी ग्रांट दी गयी है—31,725 /रु० और नम्बर आफ सेण्टर चला रहे हैं... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN: Not necessary. You can send information to the Member in a letter.

Next question.

Unemployed Doctors

*26. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of unemployed doctors in the country as on October 31, 1986;

(b) whether there is a proposal to ban private practice by doctors in Central Government service; and

(c) whether government plan to send doctors to work in villages and remote areas such as tribal areas by offering incentives?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY